देवेंद्र सिंह और अन्य

बनाम

स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य

(सिविल अपील संख्या 6293/2011)

3 अगस्त 2011

[जी. एस. सिंघवी व एच. एल. दत्तू, जजेज]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:

धारा 4 आर/डब्ल्यू एस। 17 (4), धारा 6 आर/डब्ल्यू. धारा 17 (1), और धारा 5- ए जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण- जो एक सार्वजनिक उद्देश्य है, अपने आप में उचित नहीं होगा धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करने की शक्ति का प्रयोग

1. धारा 17 के तहत तात्कालिक प्रावधानों को लागू करना और वितरण करना धारा 5 ए प्रतिपादित किया (माना गया) जिला जेल के लिए भूमि का अधिकरण, जो एक सार्वजनिक उद्देश्य है। अपने आप में धारा 5 ए के तहत जांच को खत्म करने की शक्ति के प्रयोग को उचित नहीं ठहराया। धारा 17(1) और धारा 17(4) न्यायालय स्वयं को इस तत्य का न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए कि कुछ सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे कि आवासीय,

वाणिज्य, औद्योगिक या संस्थागत क्षेत्रों का विकास उनकी आंतरिक प्रकृति और चरित्र द्वारा योजना निष्पादन आदि क्रियान्वयन पर विचार करना है। जिन योजनाओं में आम तौर पर कुछ वर्षो का समय लगता है। इसलिए उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिकरण अधिनियम के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू करने का औचित्य नही है। तत्काल मामले, घटनाओं की श्रृख्ंाला राज्य सरकार की सुस्ती और उदासीन रवैया को दर्शती है। अधिनियम की धारा 17 के तहत तात्कालिक प्रावधाानों को लागू करने के लए उचित नहीं है। जिसमें भूमि मालिकों को धारा 5ए के तहत आपत्तियां उठाने और अधिकारियों के समक्ष सुनवाई का अवसर देने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन्हे यह समझाने के लिए कि उनकी संपति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता- उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद कर दिया गया - न्यायिक संज्ञान

2 अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की - और धारा 4 सपठित धाारा 17(4) को चुनौती दी गई और धारा 6 सपठित धारा 17(1) भूमि अधिग्रहण 1894 के संबंध में जारी किया गया, की घोषणा हेतु कि उनकी भूमि के सम्बंध में धारा 5ए के तहत उन्हे सुनवाई जांच से वंचित किया गया -उच्च न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों के इस रूख को स्वीकार कर लिया भूमि का अधिग्रहण जिला जेल के निर्माण निर्माण के लिए किया गया था। यह एक अति आवश्यक मामल था और

रिट याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने जमीन मालिकों की ओर से दायर अपील को स्वीकार किया।

3. प्रतिपादित किया गया-

1.1 यह सुस्थापित हो कि धारा 17(4) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अपने आप में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के संदर्भ में धारा 5 ए के तहत जांच को समाप्त करने की कार्यकारी शक्ति को उचित नहीं ठहराया। इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए कि कुछ उद्देश्य जैसे कि आवासीय, वाणिज्यक, औद्योगिक सा संस्थागत क्षेत्रों का विकास आंतरिक प्रकृति और चरित्र के कारण योजनाओं के निष्पादन और कार्यन्वयन में आम तौर पर कुछ वर्षो का समय लगता है। इसलिए उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण अधिनियम के तहत तत्काल प्रावधानो को लागू करना नहीं है। (पैरा 9) (784 ए-सी)

1.2 वाद के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट है कि ज्योतिबा फुले नगर जिला वर्ष 1997 में था जिसे 2004 में भंग कर दिया गय था। जिला मजिस्ट्रेट ज्योतिबा नगर ने प्रिंसिपल से हमें/जेल को एक प्रस्ताव भेजा था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2000 को जिला कारागार के निर्माण हेतु अधिग्रहण निःसदेह एक सार्वजनिक उद्देश्य माना था। सन् 2008 में इतने अंतराल वर्षा के बाद, राज्य सरकार ने जिला मजिस्टेट के रूप में जिला मुख्यालय के निकट जिला जेल के निर्माण के लिए भूमि

अधिग्रहण की उपलब्धता का पता लगाया और उक्त उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने की सिफारिश करने के लिए चयन समिति की सिफारिश की। इसके बाद चयन प्रक्रिया ने जेल के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण की सिफारिश की लेकिन राज्य सकरकार को धारा 4 व 6 के तहत अधिसूचना जारी करने में दो वर्ष लग गये जिसमें अधिनियम की धारा 17 के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू किया जा सके। घटना की श्रृंखला राज्य सरकार की सुस्ती और उदासीन रवैया को दर्शाती है। इस परिस्थितियों में उजर दाताओं को अधिनियम की धारा 17 के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू करना उचित नहीं है। जिसमें अपीलकर्ता आपतियां उठाने और अधिकारियों के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने के धारा 5 ए के तहत अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित हो जाते है। उन्हे यह समझाने के लिए कि उनकी सम्पति का अधिग्रहण नहंी किया जायेगा उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाता है।(पैरा 11 और 14-15) (786 ई-एच, 787 ए-बी, 788 सी-डी)

डी देव शरण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011(3) एससी आर 728-(2011)4 एससीसी 769, और राधेश्याम बनाम उतर प्रदेश राज्य (2011)5 एस.सी. सी. 553- पर निर्भर

(ई) दीपक पटवा बनाम दिल्ली के उप राज्यपाल, 1985(1) एस.सी.आर 588 1984)4 एस.सी.बी 308 और चमेलीसिंह बनाम उत्तर

प्रदेश राज्य 1985(6) पूरक, एस.सी. आर. 827- (1996) 2 एस.सी.सी 549 प्रतिष्ठित।

वाद कानून संदर्भः

2011 (3) एससीआर 728	पर भरोसा करें	पैरा 6
(2011) 5 एस. सी. सी. 553	पर भरोसा करें	पैरा 6
1985 (1) एससीआर 588	प्रतिष्ठित	पैरा 7
1995 (6) पूरक एस. सी. आर 827	विशिष्ट	पैरा 7

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 6293/2011

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय सी. एम. डब्ल्यू. पी. सं. 61903/2010 में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 08.10.2010 से उत्पन्न।

प्रशांत कुमार (एपी एंड जे चैम्बर्स के लिए) अपीलार्थी की ओर से

के. के. वेणुगोपाल, शैल कुमार द्विवेदी, एएजी उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से

जी. वी. राव और अंकुर तलवार उत्तरदाताओं की ओर से

न्यायालय का निर्णय निम्न के द्वारा दिया गया

एच. एल. दत्तू, जे.

1. याचिका स्वीकार की गई

2. यह अपील, विशेष अनुमति के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 08.10.2010 सिविल विविध याचिका संख्या 61903/2010 में इलाहाबाद में न्यायिक न्यायालय, जिसके तहत, अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका के निर्माण के लिए उनकी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी गई भूमि की धारा 17 (1) और 17 (4) लागू करके जिला जेल अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) था बर्खास्त कर दिया।

3. वर्तमान अपील के तथ्य इस प्रकार हैंः जिला मजिस्ट्रेट ज्योतिबा फुले नगर ने प्रधान सचिव, गृह/कारागार धारा 4 को एक प्रस्ताव भेजा था। जिला जेल के निर्माण के लिए अमरोहा नौगावां सादत रोड पर स्थित भूमि के अधिग्रहण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दिनांकित पत्र 24.01.2003 5 साल के अंतराल के बाद, विशेष सचिव, जेल प्रशासन और सुधार, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट से उक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के लिए उपलब्ध भूमि खोजने का अनुरोध किया था। जिला मुख्यालय की निकटता दिनांकित पत्र के माध्यम से16.01.2008 . इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने पता लगाया और गांव दसीपुर में ऐसी भूमि की उपलब्धता की जानकारी दी और विशेष को संभावित अधिग्रहण के लिए

अन्य आस-पास के गाँव सचिव ने चयन समिति को निरीक्षण करने का निर्देश दिया उनके अधिग्रहण की व्यवहार्यता के संबंध में उपलब्ध भूमि 22.04.2008 दिनांकित पत्र के माध्यम से जेल का निर्माण। तदनुसार, चयन समिति ने उपलब्ध भूमि का विस्तृत स्थल निरीक्षण करने के बाद पाया रिपोर्ट में पाया कि गाँव दुलहर संत प्रसाद की भूमि इसके लिए उपयुक्त थी 05.05.2008 पर जेल का निर्माण। इस पृष्ठभूमि में, प्रतिवादी ने 05.03.2010 दिनांकित एक अधिसूचना जारी की थी। अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 420.870 गाँव दुल्हापुर संत प्रसाद, तहसील में हेक्टेयर भूमि निर्माण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर जिला जेल। वही स्थानीय में प्रकाशित किया गया था 26.03.2010 पर समाचार पत्र। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इसे नीचे निकाला गया हैः

" उत्तर प्रदेश शासन कारागार

प्रशासन एवम सुधार अनुभाग 4

अधिसूचना संख्या 443/22-4 के अंग्रेजी अनुवाद के बाद 2010-101 (ख) 2000 दिनांक 05 मार्च, 2010 सामान्य जानकारी के लिए जानकारीः

अधिसूचना

सं. 443/22-4-2010-101 (बी) 2000

लखनऊः तिथि 05 मार्च 2010

भूमि अधिग्रहण की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत

अधिनियम, 1894 (1984 का अधिनियम संख्या 1 (एस. आई. सी.)), राज्यपाल है -सामान्य जानकारी के लिए सूचित करना अच्छा लगता है कि भूमि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है, अर्थात् जिला जेल के निर्माण के लिए जिला ज्योतिबा फुले नगर।यह राय होना कि धारा की उप-धारा (1) के प्रावधान 17 उक्त अधिनियम की धाराएं उक्त भूमि पर लागू होती हैं - जितना कि उक्त भूमि निर्माण के लिए तत्काल आवश्यक है जिला ज्योतिबा फुले नगर में जिला जेल और यह कि तत्काल तात्कालिकता को देखते हुए जांच के कारण होने वाली देरी को समाप्त करना भी आवश्यक है उक्त अधिनियम की धारा 5-ए राज्यपाल को और प्रसन्न करती है। उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के तहत,कि धारा 5-क के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

4. चूंकि अपीलार्थियों की भूमि को भी देवेंद्र सिंह और ओआरएस में शामिल किया गया था।अधिसूचना, उन्होंने 07.04.2010 दिनांकित अभ्यावेदन किए और 20.08.2010 भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला को मजिस्ट्रेट, ज्योतिबा फुले नगर, मुख्यमंत्री और घर, नलकूप और जमीन पर

खेती की जा रही है। वे भी वैकल्पिक भूमि के बड़े क्षेत्र की उपलब्धता का सुझाव दिया एक के भीतर कोई निर्माण और सिंचाई सुविधा नहीं है।उत्तर की ओर किलोमीटर। हालांकि, संबंधित अधिकारियों ने अपीलार्थियों के इन अभ्यावेदनों का जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात, अपीलार्थी, उक्त अधिसूचना से व्यथित, उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की रिट याचिका संख्या 22252 दायर की गई इलाहाबाद में न्यायपालिका, जिसे उसके आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था दिनांकित 22.04.2010 पर योग्यता पर किसी भी मुद्दे को तय किए बिना इस आधार पर कि रिट याचिका घोषणा के रूप में अपरिपक्व है धारा 6 के तहत जारी नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा अपीलार्थियों को सभी उपलब्ध मुद्दों को उठाने की स्वतंत्रता दी गई धारा 17 (1) और 17 (4) की प्रयोज्यता सहित आधार एक बार उनकी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए अधिनियम राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद राज्य सरकार ने धारा 6 के तहत 06.08.2010 दिनांकित अधिसूचना जारी की गई अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत, इसने कलेक्टर को निर्देश दिया ज्योतिबा फुले नगर की उक्त भूमि पर कब्जा करने के लिए सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति धारा 9 (1) के तहत किसी भी पुरस्कार के अभाव में भी धारा 11 के तहत किया गया। आखिरकार, सार्वजनिक सूचना दिनांकित की गई 03.09.2010 जारी किया गया था,

जिसने इरादा व्यक्त किया था सरकार को उक्त भूमि पर कब्जा करना, जिसमें वह थी अपीलार्थियों को विशेष भूमि के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश अधिग्रहण अधिकारी, ज्योतिबा फुले नगर। अपीलार्थी, होने के नाते व्यथित, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एक रिट याचिका दायर की में न्यायपालिका ने शुद्धता पर सवाल उठाए हैं धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना की तारीख 5.3.2010 पढ़ें धारा 17 (1) के साथ पठित धारा 6 के तहत जारी धारा 17 (4) और अधिसूचना दिनांक 6.8.2010 के साथ धारा 5-ए अधिनियम के तहत के तहत सुनवाई और पूछताछ का अवसर दें। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से दिनांक 8.10.2010, ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और उत्तरदाताओं को उक्त भूमि के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी अधिनियम के संदर्भ में इस आधार पर कि निर्माण जिला जेल एक तात्कालिक मामला है जिसका उल्लेख धारा 4 के तहत अधिसूचना में किया गया है। भूमि अधिग्रहण। इस निर्णय और आदेश से व्यथित उच्च न्यायालय के, अपीलार्थी इस अपील में हमारे सामने हैं।

5. हमारे लिए वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा विचार इस प्रकार हैः क्या प्रत्यर्थी आह्वान करने में उचित है धारा 17 (1) के तहत तत्काल प्रावधान और इसके अलावा अधिनियम की धारा 17 (4) के संदर्भ में धारा 5-ए का अनुप्रयोग जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के

लिए।

6. विद्वान वकील श्री. प्रशांत कुमार प्रस्तुत किया हैं कि ज्योतिबा फुले नगर जिला अस्तित्व में आया जिला कारागार के निर्माण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण। यह केवल वर्ष 2010 में था कि राज्य सरकार ने धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 17 (1) और 17 (4) धाराओं द्वारा विचार किए गए तत्काल प्रावधान किया गया था। । दूसरे शब्दों में, अभावपूर्ण रवैया लगभग 13 साल पहले नए जिले के निर्माण के बाद से राज्य सरकार किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या चित्रण नहीं करती है। तात्कालिकता लेकिन भूमि अधिग्रहण में उनकी ओर से केवल सुस्ती। राज्य सरकार इसलिए, अधिनियम में विचार की गई तात्कालिकता नहीं हो सकती है की राज्य सरकार ओर से जिम्मेदारी की अवहेलना के बराबर विद्वान वकील का तर्क है कि उत्तरदाताओं ने अनावश्यक रूप से तात्कालिक प्रावधानों को लागू किया था अधिग्रहण के लिए धारा 17 (4) के सपठित धारा 17 (1) के तहत धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने में 13 साल की देरी को देखते हुए जिला जेल के निर्माण के लिए भूमि का अधिनियम और फिर भी, उक्त भूमि के कब्जे में है याचिकाकर्ता। विद्वान वकील का तर्क है कि धारा 17 (4) के तहत तात्कालिक प्रावधानों को लागू करना, जिसमें शामिल नहीं है की अनुपस्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा धारा 5-ए का अनुप्रयोग धारा 17 द्वारा

विचार किए गए किसी भी वास्तविक तात्कालिकता मातरा आपत्ति दर्ज करने और सुनवाई के अधिकार से अवैध रूप से वंचित करने के लिए अधिनियम की धारा 5-ए के तहत अपीलार्थी। वह इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे कानून को सख्त बनाया जाना चाहिए। निर्माण। वह आगे प्रस्तुत करता है कि धारा 5-ए एक है पर्याप्त अधिकार और मौलिक अधिकार के समान जो उचित और उचित देने के सिद्धांत को मूर्त रूप देता है भूमि मालिक को अधिकारियों को मनाने का अवसर उसकी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ जिसे दिया जा सकता है केवल वास्तविक तात्कालिकता के असाधारण मामलों में। विद्वान सलाहकार देव शरण और अन्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 4 एस. सी. सी. 769 उनके तर्क के समर्थन में जो लंबे समय तक सुस्ती को देखते हुए अधिनियम की धारा 5-ए के तहत सुनवाई और जांच का अवसर प्रदान करता है।आह्वान करके उत्तरदाताओं की ओर से लगभग 13 साल धारा 17 के तहत आपातकालीन प्रावधान अवैध है और अनुचित। विद्वान वकील ने आगे अपनी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया है जो इस न्यायालय द्वारा पहले से ही राधेश्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 5 एस. सी. सी. 553 फैसला दिया गया है।

7. कॉन्ट्रा के अनुसार, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री। के. के वेणुगोपाल प्रस्तुत करते हैं कि ज्योतिबा का नवनिर्मित जिला फुले नगर में कैदियों को रखने के लिए जिला जेल नहीं है। जिले के जो वर्तमान में समायोजित हैं मुरादाबाद जिला जेल, जिसमें कैदियों की कुल आबादी यह जेल की क्षमता से तीन गुना अधिक है, जिससे कैदियों को बहुत कठिनाई होती है। इसके अलावा, का उत्पादन मुरादाबाद जेल से ज्योतिबा के विभिन्न न्यायालयों में कैदीः फुले नगर ने वित्तीय और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उठाया है। वह प्रस्तुत करता है कि नए जिले के निर्माण के बाद से, राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है जिला जेल का निर्माण। हालांकि, बाद के कारणों से जेल के निर्माण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका अधिसूचना दिनांक 13.04.2004 के माध्यम से जिले का विघटन, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी ने विघटन की उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुसार जिले को 2004 में फिर से बनाया गया था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि राज्य सरकार ने एक धारा 4 के तहत अनुभाग के साथ पठित अधिसूचना दिनांक 5.3.2010 17 (4) नवनिर्मित जेल में तत्काल निर्माण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिनियम अधिनियम की धारा 17 (4) को लागू करके जिले को समाप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच के कारण देरी होने की संभावना है। तत्पश्चात, उक्त तात्कालिकता को देखते हुए,

राज्य ने सरकार ने अधिनियम की धारा 17 (1) के साथ पठित धारा 6 के तहत अधिसूचना दिनांक 6.8.2010 जारी की थी और इसे प्रकाशित किया था। धारा 9 के तहत एक सार्वजनिक सूचना के साथ समाचार पत्र में अधिनियम की तारीख 20.08.2010, सभी 5 महीने की अवधि के भीतर। संबंधित 03.09.2010 दिनांकित अपीलार्थियों के दावे धारा 9 के तहत भूमि का मुआवजा और माप अधिनियम के तहत, उक्त भूमि का कब्जा मोरदाबाद के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को 07.01.2011 पर सौंप दिया गया। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि कोई सुस्ती या सुस्ती नहीं है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण करने में लापरवाही नही। उन्होंने विवादित फैसले में उच्च न्यायालय के इस अवलोकन का भी समर्थन किया कि जेल का निर्माण एक तत्काल मामला है जिसमें तत्काल भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है।

धारा 17 (1) और धारा 17 (4) के तहत प्रावधान इस प्रकार अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करते हैं। वह. आगे यह तर्क देता है कि दाखिल करने का नागरिकों का अधिकार धारा 5-ए के तहत आपत्तियां और सुनवाई का अवसर हैं -

अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अधीन और उसी भूमि अधिग्रहण के लिए किसी भी तात्कालिक आवश्यकता और तात्कालिकता की स्थिति में कानूनी रूप से कटौती की जा सकती है ताकि संभावित देरी

को समाप्त किया जा सके। अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच के कारण होना। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि देव शरण का मामला (सुप्रीम) जिस पर, अपीलार्थी ने मजबूत निर्भरता रखी थी वर्तमान मामले में प्रासंगिक और लागू नहीं है क्योंकि उस मामले में, इस न्यायालय ने देवेंद्र सिंह और उनके कार्यकाल में एक नई जेल के निर्माण के लिए तत्काल प्रावधानों को लागू करके भूमि अधिग्रहण को अमान्य कर दिया। शाहजहांपुर जिले में पुरानी जेल पहले से मौजूद थी लेकिन उनके तर्कों के समर्थन में कि देरी और सुस्ती भी प्रत्यर्थियों की ओर से उन्हें अधिनियम की धारा 17 के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

8. हमारे सामने मुद्दा अब एकीकृत नहीं है जैसा कि यह है राधेश्याम के मामले में इस अदालत द्वारा पहले ही फैसला लिया जा चुका है (सुप्रीम कोर्ट) जिसमें हम में से एक पार्टी थी (जी. एस. सिंघवी, जे.) जिसमें इस न्यायालय ने विकास पर विचार किया है न्यायशास्त्र और कानून, तात्कालिकता के आह्वान के संबंध में भूमि मालिक के अधिकार की धारा 17 के तहत प्रावधान आपत्तियाँ दर्ज करें और सुनवाई और जांच का अवसर दें अधिनियम की धारा 5-ए, पहले की बहुतायत का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय के निर्णय। इस न्यायालय ने जनता के लिए भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों पर विचार किया था

इस प्रकार तात्कालिकता का आह्वान करके उद्देश्यः " प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के विश्लेषण से और विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या, निम्नलिखित सिद्धांतों को निकाला जा सकता हैः

लेना और उसे उपयुक्त बनाना सार्वजनिक उपयोग। इसे अलग तरह से रखने के लिए, संप्रभु का अधिकार है मिट्टी के किसी भी हिस्से पर अपने प्रभुत्व को फिर से स्थापित करें राज्य अपने मालिक की सहमति के बिना निजी संपत्ति को शामिल करता है बशर्ते कि ऐसा दावा जनता के कारण हो। आवश्यकता और सार्वजनिक भलाई के लिए-द्वारकादास श्रीनिवास बनाम। शोलापुर एसपीजी। और डब्ल्यूवीजी।कं.लिमिटेड, चरणजीतलाल चौधरी बनाम। भारत संघ 47 और जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य ।

(ii) राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले कानून 2 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों में आते हैं।

डीएलएफ कुतब एनक्लेव कॉम्पलेक्स शैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाम हरियाणा राज्य 49; महाराष्ट्र राज्य बनाम बी. ई. बिलिमोरिया 50, और देव शरण बनाम U.P.242 की स्थिति।

(iii) यद्यपि, प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सार्वजनिक के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है

उद्देश्य, यह याद रखना चाहिए कि अनिवार्य रूप से लेना किसी की संपत्ति एक गंभीर मामला है। अगर संपत्ति आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से संबंधित है समाज या अन्य विकलांगों से पीड़ित लोग, फिर अधिक सतर्कता, देखभाल के साथ राज्य की कार्यवाई/निर्णय और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि मालिक के भूमिहीन और वंचित होने की संभावना है उसकी आजीविका और/या आश्रय का एकमात्र स्रोत।

(iv) किसी नागरिक की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। धारा 4,5-ए और 6 के अधिदेश का पालन किए बिना राज्य और/या इसकी एजेंसियां/उपकरण अधिनियम। हालाँकि, एक सार्वजनिक उद्देश्य, जो प्रशंसनीय हो सकता है, राज्य को तत्काल प्रावधानों को लागू करने का अधिकार नहीं देता है क्योंकि वही मालिक को वंचित करने का प्रभाव डालते हैं बिना सुने संपत्ति के उसके अधिकार के बारे में। केवल एक मामले में वास्तविक तात्कालिकता की स्थिति में, राज्य तात्कालिकता का आह्वान कर सकता है भूमि मालिक या अन्य इच्छुक व्यक्तियों की सुनवाई की आवश्यकता के साथ प्रावधान और वितरण।

(v) धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 17 (1) प्रदान करती है राज्य को निजी अधिग्रहण करने की असाधारण शक्ति धारा के अधिदेश का पालन किए बिना संपत्ति 5 - ए. इन प्रावधानों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अधिग्रहण का उद्देश्य देरी को भी रोक नहीं सकता है कुछ

सप्ताह या महीने। इसलिए, इससे पहले कि धारा 5-ए का अनुप्रयोग, संबंधित प्राधिकारी को करना चाहिए पूरी तरह से संतुष्ट हो कि कुछ हफ्तों या महीनों का समय संभव है धारा 5-ए वसीयत, देवेंद्र सिंह और ओ. आर. एस. के तहत जांच करने के लिए लिया जाएगा। सभी संभावनाओं में, सार्वजनिक उद्देश्य को विफल करें जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

(vi) राज्य सरकार की संतुष्टि पर तात्कालिकता के मुददे पर विशेष वस्तु पर है लेकिन इसके लिए एक शर्त पूर्ववर्ती है धारा 17 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग और वही कर सकते हैं इस आधार पर चुनौती दी जाए कि जिसके लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा का उदेश्य बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं है उद्देश्य कि शक्ति का प्रयोग देय रूप से दूषित है दुर्भावनापूर्ण या कि संबंधित अधिकारियों ने नहीं किया अपने दिमाग को प्रासंगिक कारकों और अभिलेखों पर लागू करें।

(vii) सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग धारा 17 (1) अनिवार्य रूप से बहिष्कृत नहीं करती है - अधिनियम की धारा 5-ए जिसके संदर्भ में कोई भी व्यक्ति भूमि में रुचि रखने वाले आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और इसके हकदार हैं उनकी आपत्ति के समर्थन में सुना गया। "मे" शब्द का प्रयोग धारा 17 की उप-धारा (4) में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल सरकार को यह निर्देश देने में सक्षम बनाता है कि धारा 5-ए के तहत आने

वाले मामलों पर लागू नहीं होगी। धारा 17 की उप-धारा (1) या (2)। दूसरे शब्दों में, धारा 17 (4) का आह्वान एक आवश्यक सहवर्ती नहीं है। धारा 17 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग।

(viii) आवासीय, वाणिज्यिक के लिए भूमि का अधिग्रहण, औद्योगिक या संस्थागत उद्देश्यों को माना जा सकता है अर्थ के भीतर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण धारा 4 लेकिन यह, अपने आप में, अभ्यास को उचित नहीं ठहराती है। धारा 17 (1) और/के तहत सरकार द्वारा शक्ति या 17 (4) अदालत इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकती है कि योजनाओं की योजना, निष्पादन और कार्यान्वयन आवासीय, वाणिज्यिक विकास से संबंधित, अतः इसके लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार में निहित तात्कालिकता प्रावधान का आह्वान करके उद्देश्य धारा 17 (1)। किसी भी मामले में, ऑडी के नियम का बहिष्कार धारा 5-ए (1) और (2) में सन्निहित आल्टरम पार्टेम के नियम का बहिष्कार नहीं है। ऐसे मामलों में बिल्कुल उचित है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अच्छी तरह से तय है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अपने आप में इस अभ्यास को उचित नहीं ठहराएगी। धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करने की शक्ति अधिनियम की धारा 17 (1) और धारा 17 (4)। अदालत को करना चाहिए

इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लें कि कुछ सार्वजनिक उद्देश्य जैसे

आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या औद्योगिक विकास के रूप में संस्थागत क्षेत्र उनकी आंतरिक प्रकृति और चरित्र के अनुसार योजना, निष्पादन और कार्यान्वयन पर विचार करता है ऐसी योजनाएं जिनमें आम तौर पर कुछ वर्षों का समय लगता है। इसलिए, उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण उचित नहीं है अधिनियम के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू करना। राधेश्याम में (सुप्रीम कोर्ट), यह न्यायालय, आचरण या दृष्टिकोण पर विचार करते हुए अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार की तात्कालिकता नियोजित औद्योगिक विकास के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि जिला गौतम बुद्ध नगर में देखा गया हैः " इस मामले में विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव भेजा 2006 में कभी। स्तर तक के अधिकारी धारा 17 (1) और 17 (4)। अगर इतना समय था प्रस्ताव की प्राप्ति के बीच उपभोग किया गया भूमि अधिग्रहण और अधिसूचना जारी करना, यह नहीं है इस तर्क को स्वीकार करना संभव है कि चार से पांच सप्ताह जिसके भीतर आपत्तियाँ उप के तहत दायर की जा सकती हैं धारा 5-क की धारा (1) और उसके द्वारा बिताया गया समय कलेक्टर धारा 5-ए की उप-धारा (2) के तहत जांच करने में अधिग्रहण के इस उद्देश्य को विफल कर देते।

10. इसके अलावा, देव शरण मामले (सुप्रीम कोर्ट) में अधिग्रहण पुरानी जेल के बाद से नई जिला जेल के निर्माण के लिए भूमि भीड़भाड़ थी और स्वास्थ्य सहित कठिनाइयाँ पैदा कर रही थी और तत्काल प्रावधान

लागू करके कैदियों के लिए स्वच्छता संबंधी चिंताएँ धारा 17 के तहत इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि देवेंद्र सिंह और ओआरएस में सरकारी तंत्र ने बहुत धीमी गति से काम किया था। अधिग्रहण को समाप्त करना जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वहाँ था अधिनियम की धारा 5-ए के अनुप्रयोग को हटाने की तात्कालिकता। अदालत ने आगे कहा-उक्त शपथ-पत्र में प्रकट किए गए विभिन्न तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मामला शुरू किया गया था 6-2008, और ऐसे अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव और निर्माण निदेशक, भूमि अधिग्रहण को भेजा गया था 2-7-2008 . यह बदले में राज्य को भेजा गया था 22-7-2008 पर निदेशक द्वारा सरकार। देय राशि के बाद अग्रेषित प्रस्ताव और दस्तावेजों पर विचार करना, राज्य सरकार ने धारा 4 अधिसूचना जारी की 21-8-2008 पर धारा 17 अधिसूचना के साथ ये 24 को स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गईं। 9-2008.

36. इसके बाद, 9 महीने की अवधि में, राज्य ने सरकार ने देय मुआवजे का 10 प्रतिशत जमा किया धारा 6 की घोषणा जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया था निदेशक को, 19-6-2009 पर भूमि अधिग्रहण द. 17-7-2009 पर, और राज्य सरकार ने अंततः जारी किया 10-8-2009 पर धारा 6 घोषणा यह घोषणा थी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में 17-8-2009 पर प्रकाशित।

37. इस प्रकार प्रकाशन के बीच का समय जो बीत गया धारा 4 (1) और धारा 17 अधिसूचनाएँ, और धारा 6 स्थानीय समाचार पत्रों में घोषणा 11 महीने और 23 है। दिन अर्थात लगभग एक वर्ष। यह धीमी गति जिस पर सरकारी तंत्र ने प्रसंस्करण में काम किया था अधिग्रहण, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई तात्कालिकता नहीं थी भूमि का अधिग्रहण करना ताकि धारा 17 (4) को लागू किया जा सके। अधिनियम से।

38. रिट याचिका के पैरा 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों के बीच 11 महीने से अधिक का समय अंतराल था धारा 4 और धारा 6 अधिसूचनाएँ, जो दर्शाती हैं कि राज्य की कार्रवाई में कोई तात्कालिकता नहीं थी जो कर सकती थी याचिकाकर्ताओं को धारा 5-ए के तहत उनके अधिकार से वंचित करना। में काउंटर जो इस मामले में राज्य द्वारा पहले दायर किया गया था उच्च न्यायालय, यह विवादित नहीं था कि समय अंतराल धारा 17 के साथ पठित धारा 4 अधिसूचना के बीच, और धारा 6 की अधिसूचना लगभग 11 महीने की थी।

39. जेल का निर्माण निश्चित रूप से जनहित में है और ऐसे निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। लेकिन इस तरह अधिग्रहण केवल सख्ती से पालन करके किया जा सकता है उक्त अधिनियम का अधिदेश। इस मामले के तथ्यों में, इस तरह निम्नलिखित द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं अधिनियम की धारा 5-ए

का प्रावधान और इसके अनुसार कानून "।

11. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह यह स्पष्ट है कि ज्योतिबा फुले नगर जिले का निर्माण किया गया था वर्ष 1997 जो, हालांकि, भंग कर दिया गया था और फिर से बनाया गया था 2004 में। जिला मजिस्ट्रेट ज्योतिबा फुले नगर ने भेजा था प्रधान सचिव, गृह/कारागार को एक प्रस्ताव, यू. पी. सरकार ने 24.01.2003 पर जिला जेल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए, जो निस्संदेह सार्वजनिक है। उद्देश्य। वर्ष 2008 में 5 वर्ष बीतने के बाद, राज्य ने सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट से उपलब्धता का पता लगाने को कहा जिला कारागार के निर्माण के लिए अधिग्रहण के लिए भूमि जिला मुख्यालय से निकटता और आगे अनुरोध किया उक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त भूमि की सिफारिश करने के लिए चयन समिति। इसके बाद चयन समिति ने उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण की सिफारिश की गई जेल का निर्माण लेकिन राज्य को दो साल लग गए सरकार क्रमशः धारा 4 और धारा 6 के तहत उक्त अधिसूचनाएं जारी करेगी, जिससे तत्काल प्रावधानों को लागू किया जाएगा। अधिनियम की धारा 17 के तहत। घटनाओं की श्रृंखला सुस्ती दिखाती है और राज्य सरकार का उदासीन रवैया। रोशनी में। उपरोक्त परिस्थितियों में, उत्तरदाता उचित नहीं हैं अधिनियम की धारा 17 के तहत तत्काल प्रावधानों को लागू करने में, अधिकारियों के समक्ष आपत्तियाँ और सुनवाई का अवसर उन्हें

मनाने के लिए कि उनकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।

12. चमेली सिंह (सुप्रीम कोर्ट) मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर श्री. के. के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील उत्तरदाताओं ने निर्भरता रखी है, पहले से ही किया गया है राधेश्याम में इस न्यायालय द्वारा माना और प्रतिष्ठित किया गया निम्नलिखित शब्दों में मामला (सुप्रा): "74. यू. पी. राज्य बनाम पिस्ता देवी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वी। श्री किशन और चमेली सिंह बनाम। यू. पी. राज्य धारा में निहित तात्कालिकता प्रावधान का आह्वान 17 (1) और धारा 5-ए के अपवर्जन को मंजूरी दी गई आवास की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए न्यायालय, जिसे एक राष्ट्रीय समस्या और समाधान के रूप में माना जाता था जिनमें से राष्ट्रीय आवास नीति बनाई गई थी और दलितों, आदिवासियों को सस्ता आश्रय प्रदान करना अनिवार्य था और समाज के अन्य वंचित वर्ग।

13. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी भरोसा किया दीपक पाहवा मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय पर। उस मामले में, भूमि का अधिग्रहण जल्दबाजी में किया गया था के निर्माण के उद्देश्य के लिए धारा 17 के तहत प्रावधान दिल्ली हवाई अड्डे के लिए एक नया संचारण स्टेशन अधिसूचना से पहले सरकार के विभिन्न विभागों के बीच लगभग आठ वर्षों का पत्राचार और घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की गई

थी। इस अदालत ने कहा है कि कि केवल अधिसूचना से पहले की देरी से तात्कालिक प्रावधानों का आह्वान अमान्य नहीं हो जाएगा क्योंकि अक्सर देरी बढ़ जाती है। अधिग्रहण की आवश्यकता की तात्कालिकता। हम डरते हैं कि निर्णय उत्तरदाताओं के बचाव में नहीं आएगा क्योंकि इस न्यायालय ने कहा है कि देरी केवल तेज होती है या अधिग्रहण की आवश्यकता की तात्कालिकता को बढ़ाता है, जो रिपोर्ट तात्कालिकता केवल उस स्थिति में है जब यह पहले से ही जनता की प्रकृति में उद्देश्य मौजूद है।

14 उपरोक्त कारणों से हम मानते है कि इस मामले के तथ्यों में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17(4) के आपातकालीन प्रावधान को लागू करना उचित नही था। इसलिए अपील कर्ताओं को उनके बहुमुल्य अधिकार अधिनियम की धारा 5 ए के तहत से वंचित नहीं किया जा सकता है।

15 परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.10.2010 अपास्त किया जाता है।

राशि के संबंध में कोई आदेश नही।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी केदारनाथ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।